राम गोपाल

बनाम

नन्द लाल और अन्य

[सैयद फजल अली, मुखर्जी और चंद्र, शेखर अय्यर जेजे.]

हिंदू कानून-महिला मालिक को उपहार-निर्माण-रखरखाव के लिए उपहार-संपत्ति, चाहे पूर्ण हो या सीमित-'मलिक' शब्द का उपयोग, का प्रभाव।

किसी दस्तावेज़ को अंग्रेजी में या वर्ना कुलर में समझने में मौलिक नियम उपयोग किए गए शब्दों से इरादे का पता लगाना है; आसपास की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए लेकिन यह केवल इरादे का पता लगाने के उद्देश्य से है। उन शब्दों का अर्थ जो वास्तव में प्रयुक्त किए गए हैं। एक हिंदू महिला को एक पूर्ण संपत्ति देने के लिए, अलगाव की कोई व्यक्त शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है; यह पर्याप्त है यदि इस तरह के आयाम के शब्दों का उपयोग किया जाए जो स्वामित्व के पूर्ण अधिकारों को व्यक्त करेंगे। 'मलिक' शब्द का उपयोग जब वसीयत या अन्य दस्तावेज़ में उस पद के वर्णनात्मक रूप में किया जाता है, जिसे एक योजनाकार या कर्ता धारण करने का इरादा रखता है, तो यह वर्णन करने के लिए उपयुक्त माना जाता है कि मालिक के पास पूर्ण स्वामित्व अधिकार हैं, जिसमें अलगाव का पूर्ण अधिकार भी शामिल है, जब तक कि संदर्भ में या आसपास की परिस्थितियों में यह इंगित करने के लिए कुछ न हो कि ऐसे पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाने का इरादा नहीं था|

केवल यह तथ्य कि संपत्ति का उपहार समर्थन के लिए दिया जाता है, और एक महिला संबंध के रखरखाव को दाता के इरादे का प्रथम दृष्टया संकेत नहीं माना जा सकता है, कि दाता केवल अपने जीवन-काल के दौरान संपत्ति का आनंद लेना था। ब्याज की सीमा, जो दाता को लेनी है, दानदाता के इरादे पर निर्भर करती है जैसा कि उपयोग की गई भाषा द्वारा व्यक्त किया गया है, और यदि दस्तावेज़ में उपयोग किए

गए विशिष्ट शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं और पूर्ण स्वामित्व का आयात करते हैं, तो अनुदान का उद्देश्य, अपने आप में, ब्याज को प्रतिबंधित या कम नहीं करेगा। दाता के रखरखाव या निवास प्रदान करने की इच्छा केवल उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसने दाता को उपहार देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इसे उपहार की सीमा के माप के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता था।

जहाँ एक हिंदू दो विधवाओं को छोड़कर मर गया, एक विधवा बेटी -दामाद और एक बेटी का बेटा, और बेटी के बेटे के अभिभावक के रूप में कार्य करने वाले परिवार के एक रिश्तेदार, जो उस समय सबसे करीबी प्रत्यावर्तक था, ने बहू से संपत्ति पर अपने सभी दावों को त्यागते हुए त्याग पत्र प्राप्त किया और बदले में कुछ संपत्तियों के संबंध में उसे 'ताम्लिकनामा' का एक विलेख निष्पादित किया जो इस प्रकार थाः

"इसलिए मैंने अपनी मर्जी और स्वतंत्र इच्छा से, किसी और की ओर से किसी भी मजबूरी या जबरदस्ती के बिना, इटावा में दो मंजिला पक्की दुकान और घर और एक कोठड़ी का तामलिक बनाया। उपरोक्त नाबालिग के स्वामित्व वाली मुसम्मत (बहू) के निवास के उद्देश्य के लिए 8,000. जो पहले मास्टर के भाई सुंदर लाल को किराए पर दिया जाता है। उपरोक्त मैरी, ओहदी लाल की विधवा, एम. एस. टी. के पक्ष में, और उसे मालिक (मलिक) बना दिया।"

अभिनिर्धारित किया गया कि दस्तावेज़ के संदर्भ में या आसपास की परिधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की धारणा को विस्थापित करे, जिसे मलिक 'शब्दों का उपयोग सामान्य रूप से व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है और बहू को उपहार विलेख के तहत प्राप्त किया गया है, जिससे व्यक्त की गई संपत्तियों को एक पूर्ण वंशानुगत और हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त होता है।

राजेन्द्र प्रसाद बनाम गोपाल प्रसाद (57 आई. ए. 296), कोल्लानी कोएर बनाम वी. लुचमी प्रसाद (24 डब्ल्यू.आर. 395), टैगोर बनाम टैगोर (आई.ए. पूरक 47)

ससीमन चौधरीन बनाम शिब नारायण (49 आई.ए. 25), विश्वनाथ प्रसाद वी. चंद्रिका (60 आई.ए. 56) पर भरोसा किया।

राजा राम बक्श बनाम अर्जुन (60 आई.ए. 56), वुडयादित्ता देब बनाम मुकुंद (22 डब्ल्यू.आर. 229) प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. सूची LIX वर्ष 1949।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील 1940 की प्रथम अपील सं. 3 में दिनांक 6 सितंबर, 1943 का न्यायालय (वर्मा और यॉर्क जेजे.)।

पी.एल. बनर्जी (उनके साथ बी. बनर्जी), अपीलार्थी के लिए।

एस.पी. सिन्हा (उनके साथ एन.सी. सेन), प्रत्यर्थी के लिए के लिए।

14 नवंबर 1950.

न्यायालय का फैसला जे. मुखर्जी द्वारा सुनाया गया।

यह अपील 6 सितंबर, 1943 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक अपीलीय निर्णय के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीशों ने सिविल न्यायाधीश, इटावा के 1936 के मूल वाद संख्या 28 में किए गए निर्णय को उलट दिया था।

सिविल जज, इटावा में मूल मुकदमा संख्या 28/1936 को वादी द्वारा शुरू किया गया था, जिसने इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 की वसूली के लिए है अचल संपत्ति की दो वस्तुओं का कब्जा-एक, एक आवासीय घर और दूसरी, एक दुकान-दोनों इटावा शहर में स्थित है। इन संपत्तियों के बारे मे यह माना जाता है कि यह मंगल सेन की संपत्ति का हिस्सा था, जिसकी पिछली शताब्दी के अंत में मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे अपनी दो विधवाओं को छोड़ गया था। मिथानी और एमएसटी। रानी। मंगल सेन के छेदी लाल नाम का एक बेटा और उनकी पत्नी एम.एस.टी. से जन्मी जानकी कुर

नाम की एक बेटी थी। रानी, लेकिन दोनों उनके जीवनकाल में उनकी मृत्यु हो गई। छेदी लाल के पास कोई संतान नहीं था और वे अपनी विधवा श्रीमती से छोड़ गए। मेरिया, जबकि जानकी ने ठाकुर प्रसाद नाम का एक बेटा छोड़ा। जानकी के पति ने दूसरी पत्नी से शादी की और उनसे बाबू राम नाम का एक बेटा हुआ। मंगल सेन की मृत्यु पर, उनके हित उनकी दो विधवाओं और एम.एस.टी. पर निर्भर थे। रानी की बाद में मृत्यु हो गई, एम.एस.टी. मिथानी अपने पति की पूरी संपत्ति को एक हिंदू विधवा के प्रतिबंधित अधिकारों में रखने आई थी। 27 नवंबर 1919 को एम.एस.टी. मिथानी ने अपने पति की पूरी संपत्ति ठाकुर प्रसाद के पक्ष में उपहार के एक विलेख द्वारा समर्पण कर दी, जो उस समय सबसे करीबी प्रत्यावर्तक थे। ठाकुर प्रसाद की 1921 में मृत्यु हो गई, जिससे नंद लाल नाम का एक नाबालिग बेटा अपनी संपत्तियों में सफल हो गया और यह नंद लाल उस मुकदमे में वादी है जिसमें यह अपील की गई थी। 27 अक्टूबर 1921 को बाबू राम की ओर से और शिशु नंद लाल के अभिभावक के बीच एक ट्रांस एक्शन हुआ।

जिसके द्वारा संपत्ति की दो वस्तुओं, जो वर्तमान मुकदमे का विषय हैं, को हस्तांतरण विलेख द्वारा मेरिया को प्रेषित किया गया था, जिसे ताम्लिकनामा के रूप में वर्णित किया गया है; और उन्होंने अपनी ओर से मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के हर हिस्से पर अपने दावों का त्याग करते हुए त्याग पत्र निष्पादित किया। यह विवादित नहीं है कि मेरिया ने ताम्लिकनामा के आधार पर संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और 10 अप्रैल 1923 को उन्होंने एक वसीयत निष्पादित की, जिसके द्वारा ये संपत्तियां उनके तीन भतीजों को विरासत में दी गईं, जो उनके भाई सुंदर लाल के बेटे हैं। 19 जून 1924 को मेरिया की मृत्यु हो गई। एक राम दयाल ने इसके खिलाफ धन आदेश प्राप्त किया था। सुंदर लाल और उनके तीन बेटों, और उस आदेश के निष्पादन में मुकदमे में संपत्तियों को कुर्क किया गया और बिक्री के लिए रखा गया और उन्हें स्वयं राम दयाल ने 30 जनवरी 1934 को खरीदा था। 1 जून 1936 को, वर्तमान मुकदमा नंद लाल द्वारा

दायर किया गया था और उन्होंने इस आरोप पर संपत्ति की इन दो वस्तुओं के कब्जे की वसूली के लिए प्रार्थना की कि वे एम. एस. टी. को दिए गए थे। मेरिया अपने रखरखाव और निवास के लिए, वह केवल तब तक इसका आनंद ले सकती थी जब तक वह जीवित थी और उसकी मृत्यु के बाद, वे वादी के पास वापस आ गए। मेरिया के भाई सुंदर लाल को मुकदमे में पहला प्रतिवादी बनाया गया था और उनके तीन बेटों को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के रूप में पेश किया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 चिम्मन कुंवर नामक एक महिला है जिसके पक्ष में सुंदर लाल पर विवादित संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में हस्तांतरण के विलेख को निष्पादित करने का आरोप लगाया गया था। डिक्री धारक नीलामी खरीदार राम दयाल की मई 1935 में मृत्यु हो गई और उनकी संपत्ति उनकी बेटी के बेटे राम गोपाल के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित उपहार विलेख के तहत निहित थी। 1 सितंबर 1938 को, राम गोपाल को वादी के आवेदन पर मुकदमे में एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था और वह प्रतिवादी संख्या 6 है। दो अन्य प्रतिवादी, अर्थात् प्रतिवादी 7 और 8, जिन्हें एक ही समय में पक्षकार भी बनाया गया था, क्रमशः विधवा और राम दयाल का कथित दत्तक पुत्र हैं। मुकदमा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा लड़ा गया था, और उनके द्वारा अपने लिखित बयान में उठाए गए महत्वपूर्ण तर्क दो गुना चरित्र के थे।

पहला और मुख्य विवाद यह था कि एमएसटी। मेरिया को वादी के अभिभावक द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित 'ताम्लिकनामा' के बल पर विवादित संपत्तियों का पूर्ण अधिकार मिला और उसकी मृत्यु के बाद, संपत्तियां सुंदर लाल के तीन बेटों को हस्तांतरित कर दी गईं जो उसकी वसीयत के तहत उत्तराधिकारी थे। यह कहा जाता था कि राम दयाल ने सुंदर लाल और उनके तीन बेटों के खिलाफ एक धन आदेश के निष्पादन में इन संपत्तियों को खरीदा था और उन्हें एक वैध अधिकार प्राप्त हुआ था। दूसरा तर्क यह था कि मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। ट्रायल जज ने इन दोनों बिंदुओं का फैसला प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी के पक्ष में किया और वादी के मुकदमे को

खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में अपील करने पर, सिविल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी संख्या 6 अब इस अदालत में अपील पर आया है और श्री पियरी लाल बनर्जी, जो अपील के समर्थन में पेश हुए, ने हमारे सामने उन दोनों बिंदुओं पर जोर दिया जिन पर उच्च न्यायालय का निर्णय उनके मुवक्किल के लिए प्रतिकूल रहा है। श्री बनर्जी द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा निर्माण को बाबू राम द्वारा अपनी ओर से और साथ ही नंद लाल की ओर से निष्पादित दस्तावेज़ पर रखा जाना है, जिसके द्वारा विवादित संपत्तियों को एमएसटी को हस्तांतरित किया गया था। 'ताम्लिकनामा' के माध्यम से मेरिया। सवाल यह है कि क्या हस्तांतरणकर्ता को, इसके तहत, संपत्तियों में पूर्ण हित मिला, जो वंशानुगत और अलग-थलग थी या यह केवल एक जीवन किरायेदार का हित था। दस्तावेज़ किसी भी तरह से जटिल नहीं है। यह उन घटनाओं के पाठ से शुरू होता है जिनके तहत नंद लाल मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के एकमात्र मालिक बन गए और इस संबंध में बाबू राम और नंद लाल दोनों की ओर से "समर्थन, रखरखाव और सांत्वना" के दायित्व का उल्लेख करते हैं। मंगल सेन के पूर्व मृत पुत्र की विधवा मेरिया. दस्तावेज़ में आगे कहा गया हैः

> "इसलिए मैंने अपनी मर्जी और स्वतंत्र इच्छा से, किसी और की ओर से किसी भी मजबूरी या जबरदस्ती के बिना, अपनी उचित भावनाओं में दो मंजिला पक्की दुकान का तामलिक और एक घर बनाया है। और इटावा में एक कोठड़ी। जिसकी कीमत 8,000 रु. उपरोक्त नाबालिग के स्वामित्व वाली मुसम्मत के निवास के उद्देश्यों के लिए जो वर्तमान में एम. एस. टी. के भाई सुंदर लाल को किराए पर दिया जाता है। मेरिया ने कहा। एमएसटी के पक्ष में। मेरिया ने कहा, छेदी लाल की विधवा और उसे मालिक (मलिक) बनाया। यदि उपरोक्त उद्देश्य के लिए तामलिक बनाई गई संपत्ति का कोई हिस्सा या पूरा

हिस्सा उपरोक्त नाबालिग नंद लाल के दावे के कारण मुसम्मत के कब्जे से बाहर हो जाता है, तो मैं और मेरी हर तरह की संपत्ति इसके लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगी। इस दस्तावेज़ को त्याग पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो कि मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर अपने सभी दावों को त्यागते हुए मेरिया द्वारा निष्पादित एक समकालीन दस्तावेज़ है। त्याग पत्र जैसे ताम्लिकनामा में पिछली घटनाओं, विशेष रूप से एम.एस.टी. द्वारा निष्पादित उपहार विलेख के संदर्भ में विस्तार से पढ़ा जाता है। मिथुन ठाकुर प्रसाद के पक्ष में, मंगल सेन की पूरी संपत्ति का क्रमिक हस्तांतरण नंद लाल पर। इसके बाद यह कहा गया है कि बाबू राम ने नाबालिग के अभिभावक के रूप में और अपने स्वयं के अधिकार में भी, "इस दिन के एक ताम्लिकनामा के तहत मेरे पक्ष में एक दुकान के साथ-साथ मेरे रखरखाव के लिए एक बालखाना और एक कोटा और मेरे निवास के उद्देश्य के लिए एक घर बनाया है जो मेरे रखरखाव के लिए काफी है।"

दस्तावेज़ में आगे कहा गया है,

"इसलिए मैंने अपनी मर्जी से उपहार विलेख में उल्लिखित पूरी संपत्ति का त्याग कर दिया है। 25, 000। मैं वाचा करता हूँ और लिखित रूप में देता हूँ कि उपरोक्त नाबालिग की संपत्ति पर मेरा कोई दावा या सरोकार नहीं है और न ही उपरोक्त संपत्ति मेरे रखरखाव भत्ते के अधीन रही है और न ही मैं किसी भी समय कोई दावा करूँगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वाद्ययंत्र की अनुसूची मंगल सेन के सभी गुणों की एक सूची देती है, जिसके संबंध में एम.एस.टी. मिथानी ने ठाकुर प्रसाद के पक्ष में उपहार के एक विलेख को निष्पादित किया, जिसमें

संपत्ति कवर की दो वस्तुएं शामिल थीं। किसी दस्तावेज़ को अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में समझने में मौलिक नियम यह है कि उपयोग किए गए शब्दों से इरादे का पता लगाया जाए; आसपास की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन यह केवल उन शब्दों के इच्छित अर्थ का पता लगाने के उद्देश्य से है जो वास्तव में उपयोग किए गए हैं (') वर्तमान मामले में अनुदान के साधन को' ताम्लिकनामा 'के रूप में वर्णित किया गया है जिसका अर्थ है एक दस्तावेज जिसके द्वारा' मलिकी 'या स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित किए जाते हैं और दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुदानकर्ता को' मलिक 'या मालिक बनाया गया है। उपहार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाने के लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं हैं; और न ही दूसरी ओर, ऐसा कोई कथन है कि हस्तांतरणकर्ता केवल अपने जीवनकाल के दौरान संपत्तियों का आनंद लेगा और वे उसकी मृत्यु के बाद अनुदानकर्ता को वापस कर दिए जाएंगे।

यह पूरी तरह से तय किया जा सकता है कि कानून के इस प्रस्ताव के लिए कोई वारंट नहीं है कि जब किसी हिंदू महिला को अचल संपत्ति का अनुदान दिया जाता है, तो उसे ऐसी संपत्ति में पूर्ण या विदेशी हित नहीं मिलता है, जब तक कि ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से उसे प्रदान नहीं की जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति मित्तर द्वारा कोल्लानी कोएर बनाम लुचमी प्रसाद (') मामले में अपनाया गया तर्क, जिसे न्यायिक समिति द्वारा कई निर्णयों में अनुमोदित और स्वीकार किया गया था, मुझे अनुपलब्ध लगता है। टैगोर बनाम टैगोर (') के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को विरासत के

व्यक्त शब्दों के बिना एक संपत्ति दी जाती है, तो यह एक परस्पर विरोधी संदर्भ के अभाव में, हिंदू कानून द्वारा विरासत की संपत्ति होगी। यह कानून का सामान्य सिद्धांत है जिसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 8 में मान्यता दी गई है और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि हिंदू कानून के तहत एक महिला को उपहार का अर्थ एक सीमित उपहार है या इसके साथ विधवा की संपत्ति में मौजूद प्रतिबंधों या अक्षमताओं के समान है, तब तक इस सिद्धांत से हटने का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित रूप से हिंदू कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसके समर्थन में कोई पाठ नहीं दिया जा सकता है।

इसलिए, स्थिति यह है कि एक हिंदू महिला को एक पूर्ण संपत्ति देने के लिए, अलगाव की कोई व्यक्त शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है यदि ऐसे आयाम वाले शब्दों का उपयोग किया जाए जो स्वामित्व के पूर्ण अधिकारों को व्यक्त करें। श्री बनर्जी स्वाभाविक रूप से दस्तावेज़ के वर्णन को 'ताम्लिकनामा' के रूप में वर्णित करते हैं और उस ब्याज के संदर्भ में 'मलिक' या मालिक शब्द के उपयोग पर जोर देते हैं जो यह हस्तांतरणकर्ता को देने का इरादा रखता है। 'मलिक' शब्द का उपयोग भारत के कई हिस्सों में बहुत आम है और इसे निश्चित रूप से परिवहन का तकनीकी शब्द नहीं माना जा सकता है। प्रिवी काउंसिल की भाषा में, 'मलिक' शब्द 'जब वसीयत या अन्य दस्तावेज में उपयोग किया जाता है' उस पद के वर्णनात्मक के रूप में जिसे एक योजनाकार या कर्ता धारण करने का इरादा रखता है, एक मालिक का वर्णन करने के लिए उपयुक्त माना गया है, जिसके पास पूर्ण स्वामित्व अधिकार हैं, जिसमें अलगाव का पूर्ण अधिकार भी शामिल है, जब तक कि संदर्भ में या आसपास की परिस्थितियों में

> यह इंगित करने के लिए कुछ न हो कि ऐसे पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्रदान करने का इरादा नहीं था (')। यह मुझे कानून का एक पूरी तरह से सही बयान लगता है और मैं केवल यह जोड़ना चाहता हूं कि इसे उसी सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए जो न्यायिक समिति ने उसी अवलोकन के दौरान कहा था कि "भारतीय दस्तावेज़ में प्रत्येक शब्द का अर्थ हमेशा इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि इसे किस सेटिंग में रखा गया है, जिस विषय से यह संबंधित है और अनुदानकर्ता का स्थान जिससे वह अपना वास्तविक अर्थ प्राप्त करता है।"

इसलिए, हमारे सामने यह सवाल इस हद तक संकुचित हो जाता है कि क्या वर्तमान मामले में इन दो जुड़े उपकरणों के संदर्भ में या आसपास की परिस्थितियों में पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में कटौती करने के लिए कुछ है जो 'मलिक' शब्द आम तौर पर आयात करता है।

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के लिए अपने निर्णय तक पहुँचने में इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि अनुदान एम. एस. टी. के रखरखाव और निवास के लिए व्यक्त किया गया था। मारिया। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि अनुदान प्राप्तकर्ता के जीवनकाल के लिए था। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह बताया गया है कि दस्तावेज़ की भाषा से यह नहीं पता चलता है कि महिला के अलावा किसी और को भी अनुदान से लाभान्वित किया जाना था और बाबू राम द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति भी महिला को व्यक्तिगत रूप से दी गई थी। यह आगे कहा जाता है कि यदि मेरिया को 'ताम्लिकनामा' में शामिल संपत्तियों में एक पूर्ण संपत्ति दी गई थी, तो त्याग पत्र में इन दोनों संपत्तियों को फिर से शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसे उसने उसी समय निष्पादित किया था। मुझे नहीं लगता कि केवल यह तथ्य कि संपत्ति का उपहार महिला संबंधियों के समर्थन और रखरखाव के लिए दिया जाता है, दाता के इरादे का

प्रथम दृष्टया संकेत माना जा सकता है, कि दाता को केवल अपने जीवनकाल के दौरान संपत्ति का आनंद लेना था। ब्याज की सीमा, जो प्राप्तकर्ता को लेनी है, दानदाता के इरादे पर निर्भर करती है जैसा कि उपयोग की गई भाषा द्वारा व्यक्त किया गया है, और यदि दस्तावेज़ में उपयोग किए गए विशिष्ट शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं और पूर्ण स्वामित्व का आयात करते हैं, तो अनुदान का उद्देश्य, अपने आप में, ब्याज को प्रतिबंधित या कम नहीं करेगा। दाता के रखरखाव या निवास प्रदान करने की इच्छा केवल उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसने दाता को उपहार देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इसे उपहार की सीमा के माप के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता था। यह न्यायिक समिति द्वारा तुलनात्मक रूप से हाल के एक मामले में स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया गया था, जो विष्णुनाथ प्रसाद बनाम चंद्रिका (') में रिपोर्ट किया गया है। वहाँ एक हिंदू ने अपनी बहू के "समर्थन और रखरखाव" के लिए अपनी बहू के पक्ष में कुछ संपत्तियों के उपहार का एक पंजीकृत विलेख निष्पादित किया और घोषणा की कि दाता को संपत्ति (मलिक मुस्तकील) का पूर्ण मालिक रहना चाहिए और सरकारी राजस्व का भुगतान करना चाहिए। दस्तावेज़ में ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो स्पष्ट रूप से ब्याज को वंशानुगत बनाते हों या हितग्राही को अलगाव करने की शक्ति प्रदान करते हों। न्यायिक समिति द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्राप्तकर्ता ने दस्तावेज़ के तहत एक पूर्ण संपत्ति ली थी, जिसमें उसकी मृत्यु के बाद अधिकार देने वाले अलगाव को वैध बनाने की शक्तियां थीं। फैसले के दौरान, लॉर्ड ब्लेन्सबर्ग ने अनुमोदन के साथ, न्यायिक समिति के पहले के फैसले का हवाला दिया जहाँ उपहार के विलेख में आने वाले "आपके रखरखाव के लिए" शब्दों को दानदाताओं द्वारा ली गई संपत्ति के आजीवन ब्याज में कटौती करने के लिए अपर्याप्त माना गया था। यह कहा गया था, "ये शब्द यह दर्शाने में काफी सक्षम हैं कि उपहार उन्हें आराम से रहने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसका मतलब यह नहीं है कि यह रखरखाव के केवल अधिकार तक सीमित था।

प्रत्यर्थी की ओर से, राजा राम बक्स बनाम अर्जुन (') में न्यायिक समिति के निर्णय पर इस तर्क के समर्थन में भरोसा रखा गया था कि रखरखाव अनुदान में यह उपहार के दसवें हिस्से में प्रथम अधिकार है कि यह जीवन भर के लिए होना चाहिए। मेरी राय में, उद्धृत निर्णय सामान्य प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं है जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, और इसे मामले के वास्तविक तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो एक विशेष प्रकार के अनुदान से संबंधित हैं जिनकी अपनी विशेष विशेषताएं हैं। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक तालुका ने संयुक्त परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य को उसके रखरखाव के लिए कुछ गाँवों का अनुदान दिया था। परिवार को ज्येष्ठाधिकार के जबड़े द्वारा शासित किया जाता था और संपत्ति एक ही उत्तराधिकारी के पास जाती थी। ऐसे मामलों में सामान्य प्रथा यह है कि परिवार के कनिष्ठ सदस्य, जिन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता है, वे रखरखाव के प्रावधानों के हकदार हैं, जिसके लिए भूमि का आवंटन आम तौर पर उनके पक्ष में किया जाता है। आवंटित भूमि में अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा लिए गए ब्याज की सीमा पूरी तरह से विशेष मामले की परिस्थितियों पर या विशेष परिवार में प्रचलित उपयोग पर निर्भर करती है। प्रिवी काउंसिल के समक्ष मामले में वास्तव में स्थानांतरण का कोई विलेख नहीं था। यह तालुकदार द्वारा किया गया एक मौखिक कार्य था, और अनुदान की प्रकृति का निर्धारण मौखिक कार्य किए जाने के बाद ग्रेंटर द्वारा राजस्व विभाग को दिए गए नामों के परिवर्तन के लिए याचिका के पाठ और मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों से किया जाना था।वुडोया. डिट्टा देब बनाम मुकुंद (') का मामला, जिसे प्रिवी काउंसिल के फैसले में संदर्भित किया गया था और जिस पर भरोसा किया गया था, वह भी परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य के पक्ष में किए गए रखरखाव या खोरफोस अनुदान का मामला था, जहां संपत्ति निष्पक्ष थी और ज्येष्ठाधिकार के नियमों के तहत आती थी। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे अनुदान, जिनका उद्देश्य परिवार के तत्काल सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रावधान करना था, अपनी प्रकृति से

थे और अनुदानकर्ता की मृत्यु पर जमींदार द्वारा पुनर्वित्त योग्य भूमि की प्रथा के तहत भी थे, अन्यथा पूरे जमींदारी को निरंतर मांगों द्वारा निगल लिया जाएगा। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से उस प्रकार के मामलों पर लागू नहीं होता है जो हमारे सामने हैं और यह कभी भी प्रिवी काउंसिल द्वारा लागू नहीं किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णय से प्रतीत होता है।

वादी प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस संबंध में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि ताम्लिकनामा द्वारा दी गई संपत्तियों का मूल्य रु। 8, 000, जबकि मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई पूरी संपत्ति की कीमत रु। केवल 25,000। यह तर्क दिया जाता है कि पूरी संपत्ति के लगभग एक तिहाई हिस्से का पूर्ण अधिकार में उस व्यक्ति को हस्तांतरण, जो केवल रखरखाव का हकदार था, संभावना और सामान्य ज्ञान के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले के तथ्यों पर, तर्क के साथ कोई वजन जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य जो भी रहा हो, ताम्लिकनामा के तहत विधवा को जो मिला वह एक आवासीय घर और एक दुकान थी, और दुकान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति थी जिससे कोई आय होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुकान हमेशा से मेरिया के भाई सुंदर लाल के कब्जे में थी और किराया, जो उन्होंने दिया था या उसी के संबंध में भुगतान करने का वादा किया था, केवल रु। 12 प्रति माह। इसलिए इस संपत्ति की आय से मेरिया के लिए केवल एक रखरखाव भी संभव नहीं था, और यह इस निष्कर्ष का समर्थन करेगा कि संपत्ति उसे पूरी तरह से दी गई थी, न कि केवल आनंद के लिए, जब तक वह जीवित थी।

लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि इन दो दस्तावेजों को बनाने का उद्देश्य, जैसा कि आसपास की परिस्थितियों से पता चलता है, केवल एमएसटी के रखरखाव के लिए प्रावधान बनाना नहीं था। मारिया; दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए नंद लाल की उपाधि को पूर्ण करना

और उसी के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को शांत करना था। यह वह Mst हो सकता है। मेरिया, कानूनी रूप से, अपने मृत ससुर की संपत्ति से बाहर रखे जाने के अधिकार से अधिक किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर सकती थी। लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके कानूनी अधिकार चाहे जो भी रहे हों, मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के एकमात्र मालिक के रूप में नंद लाल की अपनी स्थिति पूरी तरह से निर्विवाद या किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले से मुक्त नहीं थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मेरिया के भाई सुंदर लाल दो मंजिला दुकान पर तमलिक्नामा के निष्पादन से बहुत पहले से थे और मेरिया को इसका कोई कानूनी अधिकार मिला था। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि 1920 में शिशु एन और लाल की ओर से सुंदर लाल को दुकान से बेदखल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था और शिकायत में आरोप था कि सुंदर लाल एम. एस. टी. के समय से ही किरायेदार के रूप में संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। मिथानी उससे समझौता करके। सुंदर लाल ने उस मुकदमे में दायर अपने लिखित बयान में किरायेदारी और नंद लाल की उपाधि के आरोप को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और खुले तौर पर कहा कि यह एमएसटी था। मेरिया जो मंगल सेन की संपत्ति की वास्तविक मालिक थी। मुकदमा मध्यस्थों के माध्यम से एक समझौते में समाप्त हुआ और परिणाम यह हुआ कि हालाँकि सुंदर लाल ने वादी के अधिकार को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद वाले को किराए, लागत और हर्जाने के लिए वाद में किए गए दावों को छोड़ना पड़ा। सुंदर लाल ने दुकान पर कब्जा करना जारी रखा और नंद लाल के पक्ष में एक रुपये का किराया देने का वादा करते हुए उसी संबंध में एक किराया समझौता किया। 12 प्रति माह। कुछ महीनों के बाद, तमलिक्नामा को निष्पादित किया गया और आवासीय घर के साथ यह दुकान मेरिया को मलिकी में दी गई। ताम्लिकनामा और त्याग पत्र दोनों में पाठ स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनकी ओर से सर्वोच्च चिंता है। बाबू राम, जो नाबालिग के हितों की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें आगे के सभी विवादों को समाप्त करना था जो एम. एस. टी.

द्वारा या उनकी ओर से उठाए जा सकते थे।मंगल सेन की संपत्तियों पर एन और लाल के अधिकारों के संबंध में मेरिया और उनकी उपाधि को बिल्कुल त्रुटिहीन बनाना। ऐसा लगता है कि यही कारण है कि मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा मेरिया को दिया गया था, जिससे वह आराम से रह सकती थी और उसकी रुचि रखरखाव के अधिकार तक सीमित नहीं थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुकान का कमरा, जो हमेशा सुंदर लाल के कब्जे में था, इस तमलिक्नामा में शामिल किया गया था और अनुदान दिए जाने के तुरंत बाद, सुंदर लाल ने एमएसटी के पक्ष में दुकान के संबंध में एक किराया समझौता किया। मारिया ने उसे संपत्ति का मालिक स्वीकार करते हुए यह सच है कि दस्तावेज़ में मेरिया के उत्तराधिकारियों का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और न ही यह आवश्यक है कि अलगाव की कोई स्पष्ट शक्ति दी जानी चाहिए। "मलिक" शब्द देश के इस हिस्से में बहुत आम अभिव्यक्ति है और इसका अर्थ और निहितार्थ दस्तावेज़ के निष्पादन से बहुत पहले न्यायिक घोषणाओं द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया था। यदि वास्तव में अनुदान प्राप्तकर्ता का उद्देश्य संपत्तियों में केवल जीवन हित रखना था, तो इस तरह के इरादे को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों की कोई कमी नहीं थी; जो इलाके में पूरी तरह से ज्ञात थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय कुछ हद तक इस तथ्य से प्रभावित हुआ था कि तमलिक्नामा में बाबू राम द्वारा स्वयं मेरिया को एक गारंटी दी गई थी और नंद लाल के कहने पर उसे संपत्तियों से बेदखल किए जाने की स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई और सहमत नहीं था। दस्तावेज़ में यह वाचा बाबू राम द्वारा एमएसटी को दी गई व्यक्तिगत गारंटी की प्रकृति में थी। मेरिया इस साधारण कारण से कि संपत्ति एक शिशु की थी और यह नाबालिग के अभिभावक के रूप में था कि बाबू राम कार्य करने का इरादा रखता था। यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा था कि बाबू राम आने वाले सभी समय के लिए खुद को बांध लेंगे और मेरिया के भावी उत्तराधिकारियों

को वीएच के रूप में गारंटी देंगे। संभवतः पक्षों द्वारा ऐसी किसी बात पर विचार नहीं किया गया था और दूसरे पक्ष द्वारा इस तरह के किसी भी उपक्रम पर जोर नहीं दिया गया था। लेकिन इस विशेष रूप में वाचा को व्यक्त करने का कारण जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान मामले में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर इसका कोई दूरगामी प्रभाव है। यह निर्माण के समर्थन में वादी के लिए कोई सहायता नहीं है जिसे उसकी ओर से दस्तावेज़ पर रखने की मांग की गई है।

मैं उच्च न्यायालय के फैसले में उल्लिखित अन्य तथ्य से भी बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं कि यदि संपत्तियां मेरिया को पूर्ण अधिकार में दी गई थीं, तो उन्हें त्याग पत्र की अनुसूची में फिर से शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसे मेरिया ने निष्पादित किया था। मैं यह देखने में विफल हूं कि त्याग के विलेख में संपत्तियों को शामिल करने से यह कैसे पता चलेगा कि इन संपत्तियों पर मेरिया के अधिकार प्रतिबंधित थे न कि एक पूर्ण चरित्र के। आखिरकार यह शुद्ध रूप से हस्तांतरण का मामला है और दोनों दस्तावेजों को एक ही लेन-देन के हिस्से के रूप में एक साथ पढ़ना होगा। 'तमलिक्नामा' के तहत, मेरिया को मंगल सेन की संपत्ति से पूरी तरह से दो संपत्तियां मिलीं। त्याग पत्र द्वारा, उन्होंने मंगल सेन द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियों के संबंध में रखरखाव के लिए अपने दावे को त्याग दिया, जिसमें वे दो वस्तुएं भी शामिल थीं जो उन्हें 'तमलिक्नामा' के तहत मिली थीं। उनके पक्ष में 'ताम्लिकनामा' निष्पादित होने के बाद, संपत्ति की इन दो वस्तुओं के संबंध में उनके रखरखाव के किसी भी अधिकार का दावा करने का कोई सवाल ही नहीं था। वह पूरी संपत्ति पर रखरखाव के अपने अधिकारों के बदले में इसकी पूर्ण मालिक बन गई और रखरखाव के इस अधिकार को उसने त्याग पत्र द्वारा छोड़ दिया। पूरे दस्तावेज़ के निर्माण पर, मेरा निष्कर्ष यह है कि दस्तावेज़ के संदर्भ में, या आसपास की परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की धारणा को विस्थापित कर दे, जिसे "मलिक" शब्द का उपयोग सामान्य रूप से व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए,

अपीलार्थी का पहला तर्क सफल होता है और इस बिंदु पर मेरे निर्णय को देखते हुए, दूसरा प्रश्न निर्धारण के लिए बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है।

परिणाम यह है कि अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और ट्रायल जज के निर्णय को बहाल कर दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 को सभी अदालतों में वादी से अपना खर्च वहन करना होगा। अन्य पक्षों के संबंध में लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

फजल अली जे.

मैं अपने विद्वान भाई मुखर्जी जे. द्वारा दिए गए फैसले से सहमत हूं।

जे. चंद्रसेखर अय्यर-

अपील की सुनवाई के दौरान मैंने संदेह व्यक्त किया कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार सही नहीं था। लेकिन आगे विचार करने पर, मैं पाता हूं कि मुसम्मत मेरिया के पक्ष में 'ताम्लिकनामा' (हस्तांतरण विलेख) की शर्तों और जिस संदर्भ में यह अस्तित्व में आया, उसे ध्यान में रखते हुए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। दस्तावेज़ या विलेख का नाम ज्यादा मायने नहीं रखता है। हालांकि 'मलिक' शब्द कला का शब्द नहीं है, लेकिन यह काफी बड़ी संख्या में मामलों में माना गया है, जो ज्यादातर प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा तय किया गया है, कि भारतीय दस्तावेजों में प्रयुक्त शब्द का अर्थ पूर्ण मालिक है और जब तक कि संदर्भ एक अलग अर्थ का संकेत नहीं देता है, तब तक इसका उपयोग शब्द 'उत्तराधिकारी', या 'बेटा', 'पोता' और 'महान' पोता 'को जोड़े बिना भी एक पूर्ण शीर्षक को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक, अगर दस्तावेज़ में अन्य खंड हैं जो शब्द के महत्व को नियंत्रित करते हैं और संपत्ति को सीमित कर देते हैं, तो हमें संकीर्ण अर्थ देना चाहिए; अन्यथा शब्द को अपना पूरा महत्व प्राप्त होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसा तब होता है जब ए1हम्मद शमसुल बनाम सेवक राम (') में निर्धारित व्याख्या के नियम को अनुचित

माना जाता है। 'ताम्लिकनामा' में प्रयुक्त भाषा (उदा. ॥) भाईदास शिवदास बनाम बाई गुलाब और एक अन्य (') और विष्णुनाथ प्रसाद सिंह बनाम चंडिका प्रसाद कुमारी और अन्य (') में वर्णित कार्यों की भाषा के लगभग समान है, जहां यह माना गया था कि एक पूर्ण संपत्ति दी गई थी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और सभी न्यायालयों में अपीलार्थी को खर्च के साथ ट्रायल जज की डिक्री को बहाल किया जाना चाहिए।

अपील की अनुमति दी गई।

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ताः आर के कूबा

उत्तरदाताओं के लिए एजेंटः एस.पी. वर्मा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिए अनुवाद किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।